सोमवार, 26 अप्रैल, 2010

मंत्रालय और प्रसार भारती में मतभेद बने मुसीबत

नई दिल्ली, (भाषा): संसद की एक समिति ने कहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के बीच अनेक मुद्दों पर विवाद नजर आता है, जिससे प्रसार भारती के कामकाज पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने संसद में हाल में पेश की गयी मंत्रालय की 2010-11 के लिए अनुदान की मांगों पर अपनी रिपोर्ट में कहा है, ''मंत्रालय और प्रसार भारती के बीच गतिरोध खेदजनक है। इससे उस समय प्रसार भारती के कामकाज पर असर पड़ रहा है, जबकि राष्ट्रमंडल खेल नजदीक हैं।'' रिपोर्ट में कहा गया है कि यह देखा गया कि मंत्रालय और प्रसार भारती के बीच कई मुद्दों पर असहमति है। मंत्रालय द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों की व्यावसायिक प्राप्तियों में कमी आ रही है। समिति ने

संसदीय समिति ने पेश की रिपोर्ट, मतभेदों से कामकाज प्रभावित

कहा कि हालांकि इस बाबत पूछे जाने पर प्रसार भारती के सीईओ बी.एस. लाली ने मंत्रालय द्वारा रखे गये आंकड़ों से सीधे तौर पर असहमति जताई। वहीं राष्ट्रमंडल खेलों के संबंध में उन्होंने कहा कि वह इसके लिए डीडी को मेजबान प्रसारणकर्ता नहीं बनाना चाहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार इसके अलावा विचार-विमर्श के दौरान यह पता चला कि सीईओ वर्तमान व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे जिसमें कि यह सार्वजनिक प्रसारक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रति जवाबदेह है।

इसमें कहा गया है कि उन्होंने ऑन रिकार्ड कहा कि प्रसार भारती कानून में बनाये गए प्रावधानों के तहत प्रसार भारती की जवाबदेही सीधे संसद के प्रति होगी। समिति ने कहा है कि सरकार को जल्दी से जल्दी मंत्रालय और प्रसार भारती के बीच मतभेदों को दूर करना चाहिए। खासतौर पर राष्ट्रमंडल खेलों के नजदीक होने और दूरदर्शन पर इनका प्रसारण होने के चलते प्रसार भारती की जवाबदेही के संबंध में मुद्दों को जल्दी से सुलझाया जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि प्रसार भारती इस आयोजन का विश्वस्तरीय प्रसारण करके देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरे।